शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने विभिन्न सहउद्यमों के लिए वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश-राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड गठित किया है। बोर्ड की स्थायी समिति इन दोनों राज्यों में जल विनियमन के कार्य को देखती है।

(ख) इन दोनों राज्यों को जल की निर्मुक्ति का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान चम्बल परियोजना से जल की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Clerance to irrigation projects of Tamil Nadu

5193. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government have given any clearance to the new irrigation projects of Tamil Nadu; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No new major and medium irrigation project of Tamil Nadu included in the VIII Plan has been received at the Centre for techno-economic appraisal.

(b) Does not arise.

Digging of wells by the Central Ground Water Board

5194. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Central Ground Water Board has dug any well in Tamil Nadu under the Scientific programme of ground water exploration;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Ground Water Board has any proposal to dig more wells in Orissa under the Scheme; and

(d) if so, the target set for Eighth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Ground Water Board, under its Scientific Programme of Ground Water Exploration has drilled 612 boreholes in Tamil Nadu upto March, 1994 comprising of 391 exploratory wells, 186 observation wells, 13 slim holes and 22 piezometers.

(c) Yes Sir.

(d) The tentative target for the Eighth Five Year Plan is for the drilling of 590 boreholes in Orissa. The target for drilling of boreholes are however fixed on yearly basis. During 1994-95, the Board has a target to drill 84 boreholes in the State which includes 58 exploratory wells and 26 observation wells.

लम्बित बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनायें

5195. **श्री जनार्दन यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार अलग-अलग कौन-कौन सी बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनायें लम्बित हैं तथा वे कब से लम्बित हैं और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा क्या वह धनराशि इस बजट में उपलब्ध कराई गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है तथा इन परियोजनाओं के माध्यम से कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी;

(ग) मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना-गत और गैर-योजनागत कार्यों के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि की मांग की थी; और उसे कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) इस समय राज्य-वार किन-किन जिलों में छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना चल रही है और चालू वित्तीय वर्ष में यह किन-किन जिलों में कार्यान्वित होने जा रही है; और

(ङ) शुष्क सिंचाई योजना किन-किन क्षेत्रों में चल रही है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसे किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) आठवीं योजना के शुरू में निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और विस्तार नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 102)

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट सम्बन्धी संसाधनों से स्वयं किया जाता है तथा उन्को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है जो विकास के किसी क्षेत्र या किसी परियोजना से संबंधित नहीं होती है। योजना आयोग ने वर्ष 1994-95 के लिए योजना के तहत 416.73 करोड रुपए की मांग की एवज में इस मंत्रालय को 275.47 करोड रुपए की राशि आबंटित की है तथा वित्त मंत्रालय ने गैर योजना के अंतर्गत 120.66 करोड रुपए की मांग की एवज में 95.16 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

(घ) देश में 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए आठवीं योजना में ड्रिप सिंचाई की केंद्रीय प्रायोजित योजना के वास्ते 197.10 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही है।

(ङ) "शुष्क सिंचाई योजना" नाम की कोई केंद्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना नहीं है।

Dumping of stored water of dams in Maharashtra into sea

5196. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stored water from the dams at Koyna, Chandoli and Kallanwadi in Maharashtra is dumped into the sea and into various rivers since irrigation canals have not been constructed, hence making the water unavailable for farmers; and

(b) if so, what steps Government intend to take to expedite the construction of canals so that the stored water of these dams can be utilised for agricultural purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) (a) and(b) While the Koyna Dam was completed long back, Warna dam near village Chandoli is scheduled for completion in 1994. The canal system of Warna project is scheduled to spill over beyond VIII Plan. The Project authorities have planned to release water in the Left Bank Canal for irrigation of 1,000 hectares in its initial reaches. 19.90 Thousand Million Cubic Feet of water is also proposed to be released into the river for irrigation of 50,500 hectares through lift irrigation. The Union Government is not aware of Kallanwadi dam in Maharashtra. Koyna Krishna Lift Irrigation Project, an Ongoing Major Project envisages to utilise water from Krishna river during monsoon period and from Koyna dam during non monsoon period. The project is scheduled to spill over beyond VIII Plan.

लघु सिंचाई योजनाएं

5197. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है और यह राशि वर्ष 1992-93 के दौरान दी गई राशि से कितनी कम या अधिक है;